• एहतियात...

डैम, पावर हाउस में सैटेलाइट फोन से रहेगा संपर्क

मंडी : बीते वर्ष बरसात के दौरान हुई आपदा से बीबीएमबी प्रबंधन ने बड़ा सबक लिया है। इस बार अब बरसात में डैम और पावर हाउस समेत मुख्य जगहों पर सैटेलाइट फोन से आपस में संपर्क रहेगा। ताकि किसी भी तरह की स्थिति पर तुरंत संपर्क किया जा सके। मोबाइल नेटवर्क और लैंडलाइन सेवा ठप होने की सूरत पर यह सैटेलाइट फोन अहम भूमिका निभाएंगे। भारी बरसात के दौरान पंडोह डैम लबालब भरता है। यहीं से ब्यास में पानी छोड़ा जाता है। लारजी बांध से पानी छोड़ने पर पंडोह डैम से पानी छोड़ा जाता है। बरसात के दौरान पंडोह डैम के जल स्तर पर अधिकारियों की निगरानी रहती है।

पंडोह डैम से ही बग्गी को भी टनल से होकर पानी भेजा जाता है। इसी टनल का पानी बग्गी में निकलकर बीएसएल जलाशय तक पहुंचता है। इसके बाद यह डैहर पावर हाउस तक पहुंचता है। ऐसे में पंडोह डैम, बग्गी और डैहर पावर हाउस तीनों ही प्रमुख स्थल हैं, जहां बीबीएमबी की निगरानी रहना बेहद जरूरी रहता है। बीते वर्ष बरसात में आपदा के दौरान पंडोह में कनेक्टिविटी पूरी तरह से ध्वस्त हो गई थी। सात से दस दिन के भीतर फोन मिलने की उम्मीद है। बीबीएमबी सुंदरनगर के अधीक्षण अभियंता अजय पाल ने बताया कि फोन जल्द उपलब्ध होंगे।

चौहारघाटी में अब अर्ली वार्निंग सिस्टम से बाढ़ के संभावित खतरे को शानन प्रोजेक्ट भांपेगा। इसके लिए बरोट स्थित शानन परियोजना से 20 किलोमीटर दूर बड़ा गांव के गड़सा ब्रिज के समीप आधुनिक अर्ली वार्निंग सिस्टम स्थापित होगा। वहीं, लंबाडग नदी की भी मॉनिटरिंग के लिए लोहारडी में इसी तकनीक के आधुनिक सेंसर स्थापित होंगे। करीब एक करोड़ से अधिक की धनराशि अर्ली वार्निंग सिस्टम स्थापित करने के लिए खर्च की जाएगी। प्राकृतिक आपदा से किसी भी प्रकार का जानी नुकसान न हो, इसके लिए पहली बार चौहारघाटी में इस आधुनिक तकनीक को अपनाया जा रहा है। इसके स्थापित होने के बाद किसी भी प्रकार की प्राकृतिक आपदा के संभावित खतरे पर पहले ही घंटी बजना शुरू हो जाएगी।

• मुलाकात...

जेपी नड्डा से मिले सीएम

शिमला : सीएम सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने बुधवार शाम को नई दिल्ली में केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा से भेंट की। मुख्यमंत्री ने बैठक के दौरान जेपी नड्डा को राज्य में स्वास्थ्य क्षेत्र में अधोसंरचना और चिकित्सा सुविधाओं को बेहतर बनाने की प्रदेश सरकार की प्रतिबद्धता के बारे में अवगत करवाया। मुख्यमंत्री ने राज्य के अस्पतालों में 'स्टेट ऑफ द आर्ट' चिकित्सा प्रौद्योगिकी की आवश्यकता पर बल दिय,ा ताकि प्रदेश के लोगों को आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं के लिए प्रदेश के बाहर न जाना पड़े। उन्होंने निर्माणाधीन नाहन, चंबा और हमीरपुर चिकित्सा महाविद्यालयों का कार्य पूर्ण करने के लिए धनराशि की मांग की।

उन्होंने कहा कि राज्य में विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा शिक्षा सुनिश्चित की जा रही है। उन्होंने राज्य में नर्सिंग का प्रशिक्षण पूरा करने वाले प्रशिक्षणार्थियों को सहयोग देने का भी आग्रह किया ताकि इन प्रशिक्षणार्थियों को विदेश में भी सेवाएं प्रदान करने के अवसर मिल सकें। सीएम सुक्खू ने प्रदेश की आर्थिकी में बल्क ड्रग पार्क की महत्त्वपूर्ण भूमिका तथा स्थानीय लोगों के लिए रोजगार व स्वरोजगार के अवसरों की उपलब्धता के दृष्टिगत केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री से इस पार्क का निर्माण कार्य शीघ्र सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान करने का भी आग्रह किया। केन्द्रीय मंत्री ने मुख्यमंत्री को केन्द्र से हरसंभव सहायता सुनिश्चित करने का आश्वासन दिया। प्रधान सचिव वित्त देवेश कुमार, मुख्यमंत्री के सचिव राकेश कंवर और आवासीय आयुक्त मीरा मोहंती भी बैठक में उपस्थित थीं।

सड़कों का निर्माण

बिलासपुर : हिमाचल प्रदेश में सड़कों का पुर्ननिर्माण फुल डेप्थ रिक्लेमेशन (एफडीआर) तकनीक से होगा। पहली बार बनने जा रही करीब सात किलोमीटर गाहर-केट संपर्क सड़क का पुनर्निर्माण कार्य शुरू हुआ। इस दौरान प्रदेश सरकार के तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी विशेष तौर पर मौजूद रहे। यह कार्य उत्तर प्रदेश की निर्भय कंस्ट्रक्शन कंपनी की ओर से किया जा रहा है। इस तकनीक से सड़कों की गुणवत्ता बेहतर होगी। वहीं पर्यावरण को बचाने के लिए भी एफडीआर तकनीक बेहद कारगर है।

प्रदेश सरकार की इस पहल को धरातल पर उतारने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। घुमारवीं उपमंडल के गाहर-केट संपर्क सड़क को एफडीआर तकनीक से बनाने का कार्य शुरू हो गया है। इस तकनीक से पुरानी सड़क को उखाड़कर बजरी व अन्य मटीरियल को नए तौर पर तैयार किया जाता है, जिससे नई सड़क तैयार की जाती है। तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने कहा कि पर्यावरण को बचाने के साथ गुणवत्तायुक्त स ?कें बनाने के लिए एफडीआर तकनीक बेहद कारगर है।

सेब पर डबल मार ,यूनिवर्सल कार्टन की गुणवत्ता पर सवाल

कुलदीप सिंह राठौर ने कहा कि अल्टरनेरिया बीमारी प्रदेश के कई इलाकों में महामारी का रूप धारण कर चुकी है। कुछ इलाकों में 95 फीसदी बगीचे बीमारी की चपेट में आ गए हैं।

ऐसे में प्रदेश सरकार केंद्र सरकार से बातचीत कर इसकी रोकथाम के लिए कदम उठाए। 1982-83 में भी सेब पर स्कैब बीमारी लग गई थी जिस पर समय रहते कदम उठाए गए और केन्द्र ने मदद ली गई...

● संजू/शिमला-सोलन

हिमाचल में सेब सीजन चल पड़ा है, तो साथ ही समस्याएं भी सामने आने लगी हैं। इस मर्तबा सेब को डबल मार पड़ती दिख रही है। एक तरफ जहां सेब अल्टरनेरिया नामक बीमारी की चपेट में आ गया है, वहीं यूनिवर्सल कार्टन की गुणवत्ता पर सवाल उठने शुरू हो गए हैं। इसके चलते कांग्रेस विधायक कुलदीप राठौर ने ही आवाज बुलंद की है। राठौर ने सेब पर फैली इस अल्टरनेरिया बीमारी को महामारी घोषित करने की मांग की है और केंद्र सरकार से भी सहयोग की बात कही है।

कुलदीप सिंह राठौर ने कहा कि अल्टरनेरिया बीमारी प्रदेश के कई इलाकों में महामारी का रूप धारण कर चुकी है। कुछ इलाकों में 95 फीसदी बगीचे बीमारी की चपेट में आ गए हैं। ऐसे में प्रदेश सरकार केंद्र सरकार से बातचीत कर इसकी रोकथाम के लिए कदम उठाए। 1982- 83 में भी सेब पर स्कैब बीमारी लग गई थी जिस पर समय रहते कदम उठाए गए और केन्द्र ने मदद ली गई। सरकार गम्भीरता को समझते हुए अल्टरनेरिया बीमारी की रोकथाम के लिए कदम उठाए और केंद्र से भी मुद्दे को उठाने का काम करे। हालांकि बागवानी विभाग ने टीमें भेजी हैं, लेकिन इस बीमारी को जड़ से खत्म करने के लिए अनुसंधान की भी जरूरत है। मार्केट में उपलब्ध दवाइयों की गुणवत्ता पर भी सवाल उठ रहे हैं इसकी भी मॉनिटरिंग होनी चाहिए। इसके अलावा विदेशों से आयात हो रहे सेब के पौधों पर भी शक की नजरें है इन पौधों का क्वारंटाइन होना चाहिए। उसके बाद ही बागवानों को उपलब्ध करवाने चाहिए। सेब के साथ विदेशों से बीमारियों का आयात नहीं होना चाहिए यह सरकार और बागवानी विभाग को सुनिश्चित करना है। सेब पहले ही घाटे का सौदा बनता जा रहा है ऐसे में बीमारियों के पनपने से सेब उत्पादन हिमाचल में बेहद मुश्किल हो जाएगा।

उधर, हिमाचल प्रदेश में सेब और नाशपती की पैकिंग में इस्तेमाल हो रहा है यूनिवर्सल कार्टन की गुणवत्ता पर सवाल उठने शुरू हो चुके हैं। थोड़े से भार पर यह मुड़ना शुरू हो गया है इसकी मजबूती कटघरे में खड़ी हो रही है। एक पेटी के ऊपर दो से तीन पेटीयां रखने पर ही यह मुड़ रही है। इससे बागवान और आढ़ती लदानियों की चिंताएं बढ़ने भी शुरू हो गई है। ऐसे में बागवानों को सेब मंडियों में आढ़ती और लदानियों को सेब दूसरे राज्यों की मंडियों तक पहुंचाना चुनौती पूर्ण हो चुका है यदि समय रहते इस दिक्कत को दूर नहीं किया गया तो आने वाले दिनों में बड़ी परेशानी खड़ी हो सकती है।

चौपाल पुलवाहल से आए किसान अरुण ने जानकारी देते बताया कि इस बार सेब सीजन संतोषजनक भी रहा है और दुविधाजनक भी क्योंकि यूनिवर्सल कार्टन पहली बार हिमाचल प्रदेश में आया है और इसमें सब की पैकिंग की जा रही है। उन्होंने कहा कि अभी तो किलो के हिसाब से उन्हें दाम बढ़िया मिल रहे हैं। उन्होंने कहा कि एक तरफ किसान बागवानों को फायदा यूनिवर्सल कार्टन का मिल रहा है वहीं दूसरी तरफ जो कंपनी है यूनिवर्सल कार्टन को लेकर पेटियां का गता तैयार कर रही है वह कई बार हल्की भी आ रही है, जिस कारण पेटियां एक के ऊपर एक आने पर दबती नजर आ रही है। उन्होंने कहा कि यूनिवर्सल कार्टन से पहले पेटियां मजबूत थी, लेकिन जो अब पैकिंग आ रही है वह 18 से 20 किलो की आ रही है। उन्होंने कहा कि इस बार सेब सीजन भी अच्छा हुआ है और किसानों को यूनिवर्सल कार्टन के हिसाब से 18 से 20 किलो की पैकिंग के बढ़िया दाम भी मिल रहे हैं।

• हाईकोर्ट...

हिमाचल नहीं देगा 280 करोड़

शिमला : मैसर्स अडानी पावर लिमिटेड के 280 करोड़ रुपए ब्याज सहित लौटने से जुड़े मामले में प्रदेश हाई कोर्ट ने राज्य सरकार की अपील को मंजूर कर लिया है। न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर व न्यायाधीश बीसी नेगी की खंडपीठ ने अपने निर्णय में कहा कि फाइलों पर टिप्पणियों को चुनिंदा रूप से पढ़ने और रिकॉर्ड पर अन्य प्रासंगिक सामग्री की अनदेखी के आधार पर अदानी द्वारा धन वापसी का दावा पुख्ता नहीं है। इस मद्दे पर कानूनी स्थिति पहले से ही स्पष्ट है कि फाइल पर दर्ज एक नोट महज एक नोटिंग को सरल बनाने वाला है। यह केवल किसी व्यक्ति विशेष की राय की अभिव्यक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। इसकी कोई कानूनी मान्यता नहीं है। इसे सरकार का निर्णय नहीं माना जा सकता। उल्लेखनीय है कि हाई कोर्ट की एकल पीठ ने सरकार को जंगी-थोपन-पोवारी विद्युत परियोजना के लिए जमा किए गए 280 करोड़ रुपए की राशि वापस करने के आदेश दिए थे। सरकार ने इस मामले में अपील करने में देरी कर दी थी। अत: सरकार को अपील दायर करने में हुई देरी को माफ करने की अर्जी भी देनी पड़ी थी। सरकार ने फीस वापसी के आदेशों पर रोक लगाने की गुहार भी लगाई थी, परंतु कोर्ट ने एकल पीठ के आदेशों पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था।

• चलती कार पर गिरे पत्थर...

नाहन : जिला सिरमौर के श्री रेणुकाजी तीर्थ को जोड़ने वाले नाहन-ददाहू-संगडाह सड़क पर चलती एक कार पर पत्थर गिरने से चार लोगों के घायल होने की सूचना है। एक कार नाहन से ददाहू की तरफ जा रही थी, जैसे ही कार बड़ोलिया मंदिर के समीप पहुंची तो पहाड़ी से पत्थर कार पर आ गिरे। इसके बाद घायलों को सिविल अस्पताल ददाहू पहुंचाया गया है, जहां उनका उपचार जारी है। हादसे में पदम देव भराड़ी, नेत्र सिंह धनास, विक्की सिंह पुन्नर धार और सुनील कुमार चाडना घायल हुए हैं।